

सार संक्षेप

अमेरिका के ऑपरेशन इकनामिक आउटकास्ट के खिलाफ आईसीओ पहुंचा ईरान

ईरान (जीएनएस)। ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन ने यूएन की एविएशन रेगुलेटर संस्था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (आईसीएओ) के पास अमेरिका द्वारा ईरानी एविएशन पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। तेहरान रुकी हुई उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए कूटनीतिक और कानूनी कदम उठा रहा है। ईरानी सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख अबूजर शिरौदी ने सोमवार को आईआरएनए को बताया कि ईरानी संस्था, विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर, रुकावटों को दूर करने और पहले से चल रही उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। दृढ़ता से बात करते हुए शिरौदी ने कहा कि ईरान ने दृढ़ता को औपचारिक विरोध पत्र के साथ-साथ ऐसे दस्तावेज भी सौंपे हैं जिनमें पाबंदियों के कारण उड़ानों में आई रुकावटों का ब्योरा दिया गया है।

डब्ल्यूएचओ का बयान: यमन में हथी लड़ाकों के साथ जंग में 164 की मौत, 645 घायल

यमन (जीएनएस)। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि 19 सितंबर से 26 सितंबर के बीच यमन में ईरान समर्थित हथी विद्रोहियों और यमन की सरकारी सेना के बीच जारी लड़ाई में 164 लोगों की मौत हुई और 645 लोग घायल हुए। संगठन के अनुसार, इस ताजा हिंसा की वजह से 1,80,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं, एक अलग घटना में, अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि गाजा शहर में इजराइली हमले में एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। वेस्ट बैंक में इजराइली मंत्री बेज़ेलेल स्मोलेच ने यरूशलेम के पास एक विवादित बस्ती परियोजना को 27 अक्टूबर के चुनावों तक रोकने के फैसले की आलोचना की।

डूहाब ने कहा कि यमन में ताजा आकड़ों के मुताबिक, 6 अगस्त से अब तक कुल 4,481 लोग हताहत हुए हैं, जिनमें 838 लोगों की मौत हुई है। इस महीने की शुरुआत में हथी लड़ाके यमन के तट पर आगे बढ़े और मोखा के अहम बंदरगाह शहर और रेड सी (लाल सागर) के रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों पर कब्जे से उन्हें ऊँची जगह मिल गई, जहाँ से वे बाब अल-मिन्बल जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) में गुजरने वाले जहाजों पर नज़र रख सकते हैं और उन पर हमला भी कर सकते हैं; इस रास्ते से दुनिया का लगभग 12 प्रतिशत व्यापार होता है

भारत को वीडो पॉवर दिलावे के लिए रूस ने यूएन में किया बड़ा धमाका, हिले अमेरिका, चीन समेत दुनिया के बड़े-बड़े देश मास्को (जीएनएस)। रूस और भारत की कितनी मजबूत और विश्वास से भरी दोस्ती है। आए दिन इसकी झलक देखने को मिलती रहती है। जब भी भारत पर कोई भी संकट आया तो रूस चञ्चल की तरह खड़ा दिखाई दिया। रूस ने हमेशा से ही भारत के लिए वो फैसले लिए जो इसके विकास में रफ्तार देने वाले साबित हो। रूस और भारत की दोस्ती तोड़ने के लिए अमेरिका जैसे देशों ने ना जाने कितनी कोशिशें की। लेकिन हर बार उनकी कोशिशें नाकाम ही साबित हुई।

जनता यूनियन



अधिकतम : 32° से.
 न्यूनतम : 23° से.

jantaunion@gmail.com



भारत को एशियन गेम्स के 9वें दिन 8 मेडल

जेवलिन में यशवीर को सिल्वर, रोहित को ब्रॉन्ज; श्रीशंकर, गुलवीर और ईशा ने भी जीते सिल्वर



जापान (जीएनएस)। भारत को एशियन गेम्स के 9वें दिन 8 मेडल मिले। यशवीर सिंह ने जेवलिन श्रो में 85.72 मीटर के पर्सनल बेस्ट

के साथ सिल्वर और रोहित यादव ने 84.35 मीटर के श्रो के साथ ब्रॉन्ज जीता।

इससे पहले श्रीशंकर मुरली ने लॉन्ग

जंप में 8.07 मीटर की जंप के साथ सिल्वर अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर में 3 मिनट 36.72 सेकेंड के समय के

साथ सिल्वर जीता।

सोमवार को ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर हासिल किया। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर में ब्रॉन्ज, वित्या रामराज ने 400 मीटर हर्डल्स में ब्रॉन्ज और पंकी बल्हारा ने कुराश के -78 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज जीता। इन मेडल के साथ भारत के खाते में अब 45 मेडल हो गए हैं। इनमें 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत मेडल टैली में 12वें स्थान पर है। शूटिंग में भारत के 12 मेडल हो गए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं।

ईशा ने शूटआउट में

नेपाल में पहाड़ टूटकर नदी में गिरा:रास्ते पर मलबा भरा, अब तक 14 मौत; नदी में वरुज पलटा

मुस्तांग (जीएनएस)। नेपाल के मुस्तांग जिले में रविवार को भारी बारिश के बीच पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर कालीगंडकी नदी में जा गिरा। इस घटना में 14 लोगों की मौत हुई है। वायरल वीडियो में चट्टानों और मिट्टी का पूरा मलबा कुछ ही सेकेंड में ढलान से नीचे आता दिख रहा है। देखते-देखते नदी का रास्ता मलबे से भर गया। इधर, बाढ़ का पानी बढ़ने से नारायण नदी में बंधे एक करूज शिप की रस्सी टूट गई। इसके बाद जहाज करीब 100 मीटर तक नदी के बहाव के साथ बहता हुआ चला गया और पुल के पिलर से टकरा गया। नेपाल 1 महीने में दूसरी बार भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। इससे पहले 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में बाढ़ आई थी। इसमें 1453 लोगों की मौत हुई, जबकि 5500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में नेपाल के अलग-अलग जिलों में बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं समेत 272 हादसे हुए। इन घटनाओं में 21 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग लापता हैं और 26 लोग घायल हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा भूस्खलन की 97 घटनाएं हुई हैं। इनमें 19 लोगों की मौत हुई, 4 लोग लापता हैं और 4 घायल हुए हैं।

गोल्ड गंवाया

ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर जीता। फाइनल में ईशा और चीन की जियाओ जियारुइक्सुआन के 38-38 पॉइंट रहे। इसके बाद शूटआउट हुआ, जिसमें जियाओ ने जीत दर्ज की। ईशा ने 580 अंक के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। मनु भाकर मेडल इवेंट तक नहीं पहुंच सकीं।

पारुल और वित्या को ब्रॉन्ज

पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर रेस में 15 मिनट 14.61 सेकेंड के समय के साथ ब्रॉन्ज जीता। वित्या रामराज ने

समूह की हर दीदी की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर

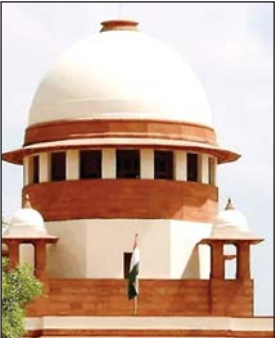
बनाना सरकार का लक्ष्य : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ जसूसं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को गौतम बुद्ध नगर में आयोजित यू.पी. इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रत्येक दीदी की आमदनी बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का संकल्प है कि कोई भी गरीब परिवार गरीबी में न रहे और गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालकर समृद्धि की ओर ले जाया जाए। स्वयं सहायता समूह इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव की महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बैंकिंग, विद्युत, कृषि, बीमा और ड्रोन सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देकर आर्थिक गतिविधियों की नई पहचान बना रही हैं। बीसी सखी, बैंक सखी, विद्युत सखी, कृषि सखी और ड्रोन सखी जैसी पहल से महिलाओं



के लिए रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। आने वाले समय में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को घरेलू गैस सिलिंडरों के वितरण से जोड़ने की दिशा में भी कार्य करने का विचार है। निर्धारित सरकारी मानकों के अनुरूप समूह की दीर्घियों के घरों पर सिलेंडरों का भंडारण एवं वितरण व्यवस्था विकसित होने से उन्हें अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिलेगा। श्री मौर्य ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए तिरंगों का उद्घाटन करते हुए कहा कि, जिन महिलाओं का भुगतान अभी लंबित है, उनका तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया रुकी हुई है तो उसे शीघ्र पूरा कर धनराशि संबंधित महिलाओं तक पहुंचाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट बोला-चुनाव आयोग 4 महीने में टीएमसी विवाद सुलझाए :पार्टी का नाम-सिंबल फीज; शिवसेना का केस 4 साल, एनसीपी का 3 साल से पेंडिंग



नई दिल्ली (जीएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नाम और 'फूल-पत्ती' चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय-सीमा तय की। कोर्ट ने दोनों गुटों को एक महीने में अपनी दलीलें पूरी करने और इसके बाद चुनाव आयोग को तीन महीने में फैसला देने का निर्देश दिया। यानी पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी

करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि वे टीएमसी विवाद को जल्दी सुलझाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करें। कोर्ट ने कहा कि इन आधुनिक तकनीकों की मदद से जटिल कानूनी दस्तावेजों को पढ़ने और समझने का काम बहुत तेजी से हो

सकता है, जिससे यह पूरा मामला 6 महीने की बजाय सिर्फ 3 महीने में ही निपटया जा सकेगा। बंगाल की दो विधानसभा सीटों नंदीग्राम और रेजीनगर में 6 अक्टूबर को उपचुनाव हैं। टीएमसी के दोनों गुटों ने असली नाम और सिंबल पर चुनाव लड़ने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के नेताओं की सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने टीएमसी नाम और चुनाव चिन्ह फीज कर दिया। आयोग ने 18 सितंबर को ममता बनर्जी के गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और 'फुटबॉल खिलाड़ी' का चिह्न दिया, जबकि दूसरे गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' और 'लिफाफा' दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का यूपीआई चार्ज पर रोक से इनकार: ₹2000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% चार्ज तय; सरकार से पूछा- नियम का आधार बताएं

नई दिल्ली (जीएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से यह शुल्क 2000 रुपए से ज्यादा के मर्चेट पेमेंट पर लागू होगा। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि इस नए नियम को लागू करने का आधार क्या है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन जजों की बेंच ने वकील अंजन दत्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता का सवाल- बिना



चर्चा के सरकार ने तय कर दिया एडवोकेट अंजन दत्ता ने जर्नहित याचिका में सवाल उठाया कि 2,000 रुपए की सीमा क्यों तय की गई? यूपीआई और रूपे कार्ड के लिए नियम अलग क्यों हैं। याचिका में इसे रद्द करने की मांग की गई थी।

याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार ने जनता से चर्चा किए बिना और कोई ठोस नियम बनाए बिना ही यह फीस तय कर दी। इसके अलावा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के एक नियम (धारा 10ए) को भी

जयपुर में ओले गिरे; यूपी में 8 नदियां उफान पर

हिमाचल में लैंडस्लाइड से नदी का बहाव रुका :केदारनाथ में 1500 लोगों का रेस्क्यू



शिमला (जीएनएस)। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सोमवार सुबह जांगलीख पुल के पास लैंडस्लाइड हो गया। 100 फीट से ज्यादा ऊंचा पहाड़ करीब 25 से 26 सेकंड तक गिरता रहा। मलबे के कारण सुंदरू नदी का बहाव भी कुछ देर

के लिए रुक गया। केदारनाथ मार्ग पर चीड़बसा में फंसे करीब 1500 यात्रियों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, और डीडीआरएफ ने रेस्क्यू कर गौरीकुंड पहुंचाया। इसके साथ ही मौसम में सुधार के बाद दो दिन से बंद चारघाट यात्रा भी फिर

शुरू कर दी गई है। जयपुर में सोमवार शाम मौसम बदला और मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाकों में ओले गिर। श्रीगंगानगर के पदमपुर के आसपास सोमवार दोपहर में बवंडर आया। वहीं, उत्तर प्रदेश में 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोंडा और बदायूं में छोटे पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। आंधी-बारिश से पिछले 2 दिनों में 63 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में 30 जून से 28 सितंबर तक 91 दिन के मानसून में नुकसान ₹3,220 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इस दौरान 373 लोगों की मौत हुई। नुकसान का मौके पर आकलन

करने के लिए 7 सदस्यीय इंटर-मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम (आईएमसीटी) सोमवार को हिमाचल पहुंची। टीम 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक राज्य का दौरा करेगी। राज्य सरकार ने मानसून से हुए नुकसान के लिए करीब ₹3,200 करोड़ की मदद मांगी है। टीम की रिपोर्ट नेशनल डिजास्टर रिसपॉन्स फंड (एनडीआरएफ) से सहायता तय करने की प्रक्रिया का हिस्सा होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सोमवार सुबह पहाड़ गिर गया। रोहड़ू के छोहरा ब्लॉक में जंगलिय पुल के पास 100 फीट से ज्यादा ऊंचा पहाड़ करीब 25 से 26 सेकेंड तक गिरता रहा। पहाड़ का मलबा सड़क पर आ

जाने से गांव का रास्ता बंद हो गया छत्तीसगढ़ के दतेवाड़ा के पास इंद्रावती नदी में बाढ़ के कारण फंसे 12 लोगों को इंडियन एयरफोर्स (आईएएफ) ने हेलिकॉप्टर से सुरक्षित बचाया। ये लोग डोंगाघाट गांव के पास नदी के किनारे कच्ची झोपड़ी की छत पर फंसे थे। बाढ़ का पानी बढ़ने से छत गिरने का खतरा था। एक गरुड़ कमांडो को छत पर उतारकर लोगों को हेलिकॉप्टर में सुरक्षित पहुंचाया गया। उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग पर चिरबासा के पास लैंडस्लाइड के कारण फंसे करीब 1500 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, और डीडीआरएफ की जाईट टीमों ने सुरक्षित निकाल लिया।

उज्जैन में मस्जिद तोड़ने के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में

खारिज :सुबह इसी पर पथराव-लाठीचार्ज हुआ, 20 पर एफआईआर

उज्जैन (जीएनएस)। उज्जैन के शाही मस्जिद मामले में दायर याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते की आधार पर मामले को डिस्मोज ऑफ कर दिया। याचिकाकर्ता शाही मस्जिद कमेटी के एडवोकेट कुलदीप पाठक ने कहा- सड़क के लिए 3 फीट जगह के साथ कुछ दुकानें हटाने पर सहमति बनी है। बड़ी मीनार को दूसरी ओर शिफ्ट किया जाएगा। दुकानों के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। इससे पहले सोमवार सुबह मस्जिद का एक हिस्सा तोड़े जाने को लेकर



जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी गई। भीड़ को हटाने के दौरान महिला थाना प्रभारी घायल हो गई। विवाद के बाद फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन दोपहर होते-होते फिर पथराव होने लगा। पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर आंसू गैस छोड़ी। हंगामे के बीच कार्रवाई जारी रही। हालांकि, नमाज के समय इसे रोक दिया गया। इसके बाद मामला शांत हो गया। पुलिस ने 3 थानों में 20 लोगों के खिलाफ 8 नामजद एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। इन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है।

जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी गई। भीड़ को हटाने के दौरान महिला थाना प्रभारी घायल हो गई। विवाद के बाद फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन दोपहर होते-होते फिर पथराव होने लगा। पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर आंसू गैस छोड़ी। हंगामे के बीच कार्रवाई जारी रही। हालांकि, नमाज के समय इसे रोक दिया गया। इसके बाद मामला शांत हो गया। पुलिस ने 3 थानों में 20 लोगों के खिलाफ 8 नामजद एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। इन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है।

cm^yk +

संपादक की कलम से

आखिर कीमत कौन चुका रहा है?

किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे मूल्यवान पूंजी केवल धन, प्राकृतिक संसाधन या बुनियादी ढांचा नहीं होती। उससे भी अधिक मूल्यवान संसाधन उसके नागरिकों का समय होता है। धन की भरपाई की जा सकती है, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसके बावजूद भारत में सार्वजनिक नीति पर होने वाली बहसों में नागरिकों के समय की आर्थिक कीमत शायद ही कभी चर्चा का विषय बनती है। सरकारी अस्पतालों की कतारें, प्रशासनिक कार्यालयों के अंतहीन चक्कर, सार्वजनिक परिवहन का अनिश्चित इंतजार और साधारण सरकारी सेवाओं के लिए घंटों की प्रतीक्षा हमारे दैनिक जीवन का सामान्य अनुभव बन चुके हैं। इस सामान्यीकरण ने एक गहरी आर्थिक समस्या को लगभग अदृश्य बना दिया है।

अर्थशास्त्री गैरी बेकर के मुताबिक, प्रत्येक घंटे की अपनी अवसर लागत होती है। अगर करोड़ों नागरिक प्रतिदिन कार्यस्थल, व्यवसाय, शिक्षा या घरेलू उत्पादक गतिविधियों से समय निकालकर केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, तो अर्थव्यवस्था प्रतिदिन लाखों उत्पादक श्रम-घंटे खो देती है। इस क्षति का उल्लेख न तो बजट दस्तावेजों में मिलता है और न ही आर्थिक विकास के आंकड़ों में, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक और स्थायी होता है।

अर्थशास्त्र में पूंजी के निष्क्रिय पड़े रहने को अक्षमता माना जाता है। यही सिद्धांत नागरिकों के समय पर भी लागू होता है। जिस प्रकार बंद पड़ा कारखाना उत्पादन घटाता है, उसी प्रकार अनावश्यक प्रतीक्षा में फंसे करोड़ों लोग राष्ट्रीय उत्पादकता को कम करते हैं। दिहाड़ी मजदूर की एक दिन की आय समाप्त हो जाती है। छोटा व्यापारी अपनी दुकान देर से खोलता है। स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति शाहकों से दूर रहता है। वेतनभोगी कर्मचारी अवकाश लेने को विवश होता है। विद्यार्थी पढ़ाई का समय खो देते हैं। प्रतीक्षा का आर्थिक प्रभाव व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़कर श्रम बाजार और राष्ट्रीय आय तक पहुंचता है। प्रतीक्षा सामाजिक असमानता का भी एक स्वरूप है। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति निजी अस्पताल, भुगतान आधारित सेवाएँ, पेशेवर एजेंट या डिजिटल सहायता के माध्यम से समय खरीद लेते हैं। सीमित आय वाले परिवारों के पास यह विकल्प नहीं होता। गरीब परिवारों के लिए समय दुर्लभ संपत्ति है। जीविका और सरकारी सेवाओं के बीच संतुलन बनाना उनके लिए निरंतर संघर्ष का विषय रहता है। इसी कारण कई विद्वान प्रतीक्षा को ‘टाइम टैक्स’ कहते हैं। इसका भुगतान सबसे अधिक वही लोग करते हैं, जिनकी आय सबसे कम होती है।

इसका एक लैंगिक आयाम भी है। परिवार के बच्चों, बुजुर्गों और बीमार सदस्यों को अस्पताल, राशन की दुकान या सरकारी कार्यालय ले जाने की जिम्मेदारी प्रायः महिलाओं पर आती है। प्रतीक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त घंटा उनके अवैतनिक देखभाल कार्य को बढ़ाता है। परिणामस्वरूप शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और औपचारिक श्रम बाजार में उनकी भागीदारी प्रभावित होती है। समय का असमान वितरण आर्थिक असमानता को और गहरा कर देता है।

व्यावहारिक अर्थशास्त्र इस समस्या को एक अलग दृष्टि से देखता है। लोग केवल उपलब्ध सेवाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि उस प्रक्रिया की अनुमानित कठिनाई को भी ध्यान में रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि सरकारी अस्पताल में पूरा दिन लग जाएगा, तो वह उपचार टाल सकता है। किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, तो पात्र नागरिक भी आवेदन करने से बच सकते हैं। इस तरह प्रतीक्षा सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को भी सीमित कर देती है।

यह प्रश्न लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता से भी जुड़ा है। नागरिक जब बार-बार अस्पष्ट प्रक्रियाओं और प्रशासनिक विलंब का सामना करते हैं, तब सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति उनका विश्वास धीरे-धीरे कम होने लगता है। सार्वजनिक विश्वास किसी भी अर्थव्यवस्था की अदृश्य पूंजी होता है। संस्थाओं पर भरोसा जितना अधिक होता है, नीतियों का अनुपालन उतना सहज होता है और शासन की लागत भी उतनी कम रहती है। एस्टोनिया, सिंगापुर इत्यादि देशों में प्रशासनिक सफलता का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि किसी व्यक्ति को अपना वैध कार्य पूरा करने में कितनी कम ऊर्जा और कितना कम समय व्यय करना पड़ता है। भारत को भी समय को सार्वजनिक संसाधन के रूप में स्वीकार करना होगा। आर्थिक प्रगति की चर्चा तब तक अधूरी रहेगी, जब तक नागरिकों के समय को भी राष्ट्रीय संपदा के रूप में महत्व नहीं दिया जाएगा।

=====

मेजों पर पानी का राज़...!

गरीब देश की ऊँची कुर्सी, अफसरशाही का अंदाज़, जनता प्यासी, सूखे हलक, मेजों पर पानी का राज़। कहीं नलों में पानी गायब, कहीं सूखें खेत-खलिहान, कहीं घड़ों में दरारें पड़तीं, कहीं %बोतलों% का सम्मान। 500 रुपये लीटर की चर्चा, बोतल कीमत आसमान, इस देश में हर बूँद की कीमत, इतना महँगा जलपान! चुनावों की बड़ी-बड़ी बैठक, लोकतंत्र का भारी काम, जनता के विश्वास की खातिर, हर दिन है नया पैगाम। ना विरोध किसी के जल का, ना किसी सुविधा से बैर, जनता के धन का हिसाब हो और पारदर्शिता की खैर। कुर्सी चाहे जितनी ऊँची हो, जनता से ऊँचा कोई नहीं, सेवा-संकल्प जीवित हो, वहाँ दिखावे की जगह नहीं। 500 लीटर या पाँच बोतल, प्रश्न उठे तो जवाब भी दो, जनता के विश्वास की खातिर, हर खर्च का हिसाब दो। लोकतंत्र की ये पुकार है, जनता ही असली सरकार है, पानी की हरेक बूँद बचाने में, देश का सच्चा संस्कार है!

- संजय एम तराणेकर



महेन्द्र तिवारी

पिछले कुछ वर्षों में चरम मौसमीय घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ी हैं। पहले जहाँ किसी क्षेत्र में एक दशक में एक बार भीषण बाढ़ आती थी, वहीं अब ऐसी घटनाएँ कुछ ही वर्षों के अंतराल पर दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार लंबे समय तक चलने वाली लू, असामान्य ठंड, समुद्री तूफान और जंगल की आग अब अलग-अलग घटनाएँ नहीं रह गई, बल्कि बदलते जलवायु तंत्र की परस्पर जुड़ी हुई कड़ियाँ बन गई हैं। इसी प्रकार लंबे समय तक चलने वाली लू, असामान्य ठंड, समुद्री तूफान और जंगल की आग अब अलग-अलग घटनाएँ नहीं रह गई, बल्कि बदलते जलवायु तंत्र की परस्पर जुड़ी हुई कड़ियाँ बन गई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक जलवायु चक्र हमेशा से मौजूद रहे हैं, किंतु जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और औद्योगिक उत्सर्जन ने पृथ्वी के तापमान को इतना बढ़ा दिया है कि प्राकृतिक घटनाएँ पहले की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी रूप ले रही हैं।

एशिया इस संकट का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बनता जा रहा है। यहाँ विश्व की लगभग 60 प्रतिशत आबादी निवास करती है और बड़ी संख्या में लोग नदियों, समुद्री तटों तथा पर्वतीय क्षेत्रों पर निर्भर हैं। दक्षिण एशिया में मानसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा से नदियाँ उफान पर हैं तो कहीं वर्षा की कमी से खेत सूख रहे हैं। जापान, चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक हिस्सों में भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में तीव्र वर्षा के कारण मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और पूरे गाँव खतरे की चपेट में आ जाते हैं। यह स्थिति केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि अनियोजित निर्माण, वनों की कटाई और असंतुलित भूमि उपयोग से भी जुड़ी हुई है।

यूरोप की तस्वीर बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, किंतु संकट उतना ही गंभीर है। फ्रांस, स्पेन और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों ने वर्ष 2026 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का अनुभव किया। फ्रांस में जुलाई का औसत तापमान 126 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक दर्ज किया गया। कई क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से बहुत कम रही, जिससे नदियों का जलस्तर घटा और जंगल सूखने लगे। सूखी वनस्पति तथा तेज हवाओं ने जंगल की आग को भयंकर रूप दे दिया। हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुए और अनेक समुदायों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। यह संकेत

नुकसान पहुंचाने पूरा वातावरण है गुलज़ार, अपने दिल का खुद ही रखें ख्याल

आज के आधुनिक युग में मनुष्य ने भौतिक सुख के चक्कर में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ समझौता कर लिया हैं। जिधर देखो उधर अनेकितक, स्वाथं, होखाघड़ी का साम्राज्य फैला हुआ हैं। कहीं घमसे ऊंची आवाज में भी बात करें तो हम पलटकर उल्टा जवाब देते या वादविवाद करते है, परंतु कोई मिलावटखोरी, प्रदूषण, अस्वच्छता के द्वारा हमें महंगे लाइलाज जानलेवा बीमारियां भी दे दे तो हम उफ़ तक नहीं करते, क्योंकि हमने अपनी मानसिकता को उस प्रकार से ढाल दिया हैं। हम केवल प्रत्यक्ष रूप से होनेवाली समस्या के लिए थोड़े-बहुत जागरूक होते है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जानेवाली हमारी जान की हमें कभी परवाह ही नहीं होती। बढ़ती मानवीय लालसा ने पुरे पृथ्वी पर दूषित वातावरण का चक्रव्यूह रचा है, जिसने समस्त जीवसृष्टि को घातक बीमारियों से जकड़ा हैं। असमय होनेवाली मौतों में बेतहाशा वृद्धि ने भयावह रूप दर्शाया है, परंतु मनुष्य है कि समस्या ही नहीं चाहता। ऐसे लोगों की गलती की सजा अन्य मासूमों को भी अपनी जान गवांकर चुकानी पड़ती है।

दूषित वातावरण के कारण आज तेजी से जानलेवा बीमारियां बढ़ी हैं। कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक बीमारियों के नाम अब हमें रोजाना ही सुनने मिलते हैं। एकदम स्वस्थ मनुष्य जो, नशा नहीं करता है, हमेशा पोषक आहार लेता है, बेहतर निरोगी जीवशैली का अनुसरण करता है, ऐसे मनुष्य भी घातक बीमारियों से जान गवां रहे है, क्योंकि निकट दर्ज की खाद्य पदार्थों की भरमार, मिलावटखोरी और दूषित वातावरण में सांस लेने को मजबूर हैं। हमारी चटोरी जुबान के स्वाद के लालच में पशुओं के लायक भी न हों ऐसे खाद्य पदार्थ हम बड़े चटकारे लेकर खाते है और समस्त शरीर को कूड़ेदान बनाते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल तो अब हमारे शरीर का हिस्सा बन गया हैं। हमारे देश में तो मीठ, मैदा, मसाला, तेल, नमकीन बगैर दिनचर्या ही पूरी नहीं होती, जबकि यह बेहद घातक हैं। बढ़ता मोटापा, आलस्य, लंबे समय तक बैठकवाला कार्य अधिक मुश्किलें बढ़ाता हैं। बीमारी के कारण बढ़ता आर्थिक तनाव और मानसिक अस्वस्थता भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। उन्नत देशों ने जिस खाद्य पदार्थो या उत्पादों पर बैन लगाया है, वह भी हमारे देश में धड़ल्ले से बिकते हैं। जानलेवा रसायनों का खाद्य पदार्थों में प्रयोग और नकली खाद्यपदार्थ बाजारों को गुलजार बना रहे हैं।

लालची व्यापारी या दुकानदार अपने एक रुपये के फायदे के लिए भी मासूमों के जान से खिलवाड़ करने से नहीं छूटते। तुकराम मुंडे महाराष्ट्र राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन

जलवायु संकट अब केवल वैज्ञानिकों की शोध रिपोटों या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का विषय नहीं रह गया है। यह आज करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। एशिया में अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़, यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और जंगलों की आग, अफ्रीका में सूखा तथा अनेक देशों में अनिश्चित वर्षा का क्रम यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी का जलवायु तंत्र तेजी से बदल रहा है। वर्ष 2026 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा विभिन्न जलवायु निगरानी संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान औद्योगिक युग से पहले की तुलना में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के बेहद निकट पहुंच गया है। यह केवल एक आँकड़ा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के सामने खड़ी सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती का संकेत है।

पिछले कुछ वर्षों में चरम मौसमीय घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ी हैं। पहले जहाँ किसी क्षेत्र में एक दशक में एक बार भीषण बाढ़ आती थी, वहीं अब ऐसी घटनाएँ कुछ ही वर्षों के अंतराल पर दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार लंबे समय तक चलने वाली लू, असामान्य ठंड, समुद्री तूफान और जंगल की आग अब अलग-अलग घटनाएँ नहीं रह गई, बल्कि बदलते जलवायु तंत्र की परस्पर जुड़ी हुई कड़ियाँ बन गई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक जलवायु चक्र हमेशा से मौजूद रहे हैं, किंतु जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और औद्योगिक उत्सर्जन ने पृथ्वी के तापमान को इतना बढ़ा दिया है कि प्राकृतिक घटनाएँ पहले की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी रूप ले रही हैं।

एशिया इस संकट का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बनता जा रहा है। यहाँ विश्व की लगभग 60 प्रतिशत आबादी निवास करती है और बड़ी संख्या में लोग नदियों, समुद्री तटों तथा पर्वतीय क्षेत्रों पर निर्भर हैं। दक्षिण एशिया में मानसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा से नदियाँ उफान पर हैं तो कहीं वर्षा की कमी से खेत सूख रहे हैं। जापान, चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक हिस्सों में भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में तीव्र वर्षा के कारण मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और पूरे गाँव खतरे की चपेट में आ जाते हैं। यह स्थिति केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि अनियोजित निर्माण, वनों की कटाई और असंतुलित भूमि उपयोग से भी जुड़ी हुई है।

यूरोप की तस्वीर बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, किंतु संकट उतना ही गंभीर है। फ्रांस, स्पेन और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों ने वर्ष 2026 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का अनुभव किया। फ्रांस में जुलाई का औसत तापमान 126 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक दर्ज किया गया। कई क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से बहुत कम रही, जिससे नदियों का जलस्तर घटा और जंगल सूखने लगे। सूखी वनस्पति तथा तेज हवाओं ने जंगल की आग को भयंकर रूप दे दिया। हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुए और अनेक समुदायों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। यह संकेत

जलवायु संकट की वैश्विक चुनौती

है कि विकसित देश भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित नहीं हैं।

जलवायु संकट की जड़ में बढ़ता वैश्विक तापमान है। वैज्ञानिक आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 का जुलाई महीना इतिहास के दूसरे सबसे गर्म जुलाई महीनों में शामिल रहा। महासागरों की सतह का तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र का गर्म होना केवल समुद्री जीवों की समस्या नहीं है। यही गर्म महासागर अधिक जलवाष्प उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण कहीं मूसलाधार वर्षा और कहीं अधिक शक्तिशाली चक्रवात बनने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार समुद्र और वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हुए चरम मौसम की घटनाओं को और तीव्र बना देते हैं।

इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण कारक अल नीनो रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार प्रशांत महासागर में विकसित हो रहा मजबूत अल नीनो अगस्त से अक्टूबर तक विश्व के मौसम को प्रभावित कर सकता है। इसके कारण अनेक क्षेत्रों में सामान्य से अधिक गर्मी तथा वर्षा के पैटर्न में बड़े परिवर्तन की आशंका व्यक्त की गई है। भारत सहित कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा की संभावना है, जबकि पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप के कुछ भागों में अधिक वर्षा हो सकती है। यह स्पष्ट करता है कि जलवायु संकट केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक वायुमंडलीय और समुद्री प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है।

जलवायु परिवर्तन का सबसे गहरा प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है। किसान सदियों से मौसम के निश्चित चक्र पर निर्भर रहे हैं, किंतु अब बोआई और कटाई का समय अनिश्चित होता जा रहा है। अत्यधिक वर्षा से फसलें जलमग्न हो जाती हैं, जबकि लंबे सूखे से उत्पादन घट जाता है। चावल, गेहूँ, मक्का और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। इसके साथ ही कीटों और रोगों का प्रसार भी बदलते तापमान के कारण नए क्षेत्रों तक पहुँच रहा है। परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव बढ़ रहा है।

जल संकट भी इस चुनौती का महत्वपूर्ण पक्ष है। हिमालयी हिमनदों का पिघलना प्रारंभिक वर्षा में नदियों में जल बढ़ा सकता है, किंतु दीर्घकाल में यही स्थिति जल उपलब्धता को कम कर सकती है। दूसरी ओर अत्यधिक वर्षा का अधिकांश पानी तेजी से बह जाता है क्योंकि शहरों में प्राकृतिक जल निकासी तंत्र नष्ट हो चुके हैं। महानगरों में कुछ घंटों की वर्षा ही जलभराव और यातायात ठप होने का कारण बन जाती है। इसका समाधान केवल बड़े बाँध नहीं, बल्कि वर्षा जल संचयन, आर्द्रभूमियों का संरक्षण और प्राकृतिक जल मार्गों की पुनर्स्थापना में निहित है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जलवायु संकट गंभीर खतरा बन चुका है। लगातार बढ़ती गर्मी से हीट स्ट्रोक, हृदय रोग

और श्वसन संबंधी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। जंगल की आग से निकलने वाला धुआँ हजारों किलोमीटर दूर तक वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। बाढ़ के बाद दूषित जल के कारण जलजनित रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और बाहर काम करने वाले श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन अब पर्यावरण के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी विषय बन चुका है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो चरम मौसम विकास की गति को धीमा कर सकता है। सड़कें, पुल, रेल मार्ग, बिजली तंत्र और संचार व्यवस्था बार बार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। बीमा कंपनियों पर दावों का बोझ बढ़ता है और सरकारों को राहत तथा पुनर्वास पर भारी खर्च करना पड़ता है। पर्यटन, मत्स्य पालन औ वानिकी जैसे क्षेत्र भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। विकासशील देशों के लिए यह दोहरी चुनौती है क्योंकि उन्हें एक ओर आर्थिक विकास बनाए रखना है और दूसरी ओर जलवायु अनुकूल आधारभूत ढाँचे में निवेश भी करना है।

इस संकट से निपटने के लिए केवल वैश्विक घोषणाएँ पर्याप्त नहीं हैं। सबसे पहले कार्बन उत्सर्जन में वास्तविक कमी लानी होगी। सौर, पवन और जल आधारित स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, ऊर्जा दक्ष भवन, वनों का संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ दीर्घकालिक समाधान का आधार बन सकती हैं। साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को गाँव गाँव तक पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मानना है कि समय पर चेतावनी मिलने से आपदाओं से होने वाली जनहानि में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

भारत जैसे देशों के लिए जलवायु न्याय भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों का उत्सर्जन अधिक रहा है, जबकि विकासशील देश जलवायु प्रभावों का बड़ा बोझ उठा रहे हैं। इसलिए जलवायु वित्त, हरित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत आवश्यक हैं। यदि वैश्विक समुदाय साझा जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आगे बढ़े, तभी पेरिस समझौते के लक्ष्यों को व्यवहार में बदला जा सकेगा और संवेदनशील देशों को अनुकूलन के लिए पर्याप्त संसाधन मिल पाएँगे।

आज बाढ़, सूखा, लू और जंगल की आग हमें एक ही संदेश देते हैं कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने की कीमत पूरी मानवता चुका रही है। जलवायु संकट किसी एक देश, महाद्वीप या पीढ़ी की समस्या नहीं है। यह हमारे विकास मॉडल, ऊर्जा उपयोग और प्राकृतिक जलवायु वित्त, हरित प्रौद्योगिकी का सामूहिक परीक्षा है। यदि समय रहते वैज्ञानिक नीति, जनभागीदारी और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी जीवन शैली अपनाई जाए तो इस संकट के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अन्यथा आने वाले वर्षों में चरम मौसम अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य वास्तविकता बन जाएगा।

कांग्रेस-सपा के बीच सीट बंटवारे से पहले खिंची तलवारें

उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन पर 2027 की फसल अभी तैयार

नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हिस्सेदारी को लेकर काट-छांट शुरू हो गई है। ऊपर से दोनों दल साथ दिखाई देना चाहते हैं, नीचे कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच यह मतभेद तेजी से उभर रहा है कि गठबंधन में किसकी जमीन कितनी और किसकी सीट बंटवारे को महज चुनावी समझौते के बजाय दोनों दलों की राजनीतिक हसियत की लड़ाई बना दिया है।सितंबर के आखिरी सप्ताह में जिस तरह इमरान मसूद, इकरा हसन, अजय राय और दूसरे नेताओं के बयान सामने आए, उससे यह साफ है कि आसमानी बेचैनी सीटों की संख्या से पहले नेतृत्व और प्रभाव क्षेत्र को लेकर है। इमरान मसूद लगातार जल्द सीट बंटवारा तय करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देरी का नुकसान जमीन पर हो रहा है। इकरा हसन ने जवाब में सपा को उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ बड़ी ताकत बताया और कांग्रेस के अकेले लड़ने की स्थिति पर सवाल उठाए। अजय राय ने इसे इकरा की निजी राय बताया। यानी गठबंधन बना रहने की बात अपनी जगह है, लेकिन गठबंधन के भीतर राजनीतिक वर्चस्व की बहस खुलकर बाहर आ चुकी है।

अखिलेश यादव ने इस बयानबाजी को रणनीतिक का हिस्सा बताया है। रायबरेली में उनकी पीडीए यात्रा और उसके जवाब में कांग्रेस की ओर से इटावा, कन्नौज और सैफई में कार्यक्रम की बात भी इसी राजनीतिक रस्साकशी का विस्तार है। सहरयोी दल यदि एक-दूसरे के प्रभाव में सपा यह क्यों चाहेंगी कि जिन सीटों पर केवल मंच तक नहीं रहता, वह सीट बंटवारे की मेज तक पहुंचता है।कांग्रेस की मुश्किल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने उसे उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी का आधार दिया है, लेकिन विधानसभा के आंकड़े उसकी स्थिति को अलग कहानी में रखते हैं। 2024 में सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटें जीतीं। दोनों की संयुक्त संख्या 43 रही, जबकि भाजपा 33 पर रही। सपा का मत प्रतिशत 33.59 और कांग्रेस का 9.46 प्रतिशत था। पांच साल पहले 2019 में सपा के पास पांच और कांग्रेस के पास केवल एक लोकसभा सीट थी। यानी 2024 ने विपक्षी गठबंधन को नई जिंदगी बर्बाद न करें। जिंदगी फिर नहीं मिलती, स्वास्थ्य ही धन हैं।

संजय सत्सेना

सफलता को विधानसभा सीटों में सीधे बदलना संभव नहीं है। क्योंकि विधानसभा का गणित कहीं अधिक स्थानीय है। 2022 में भाजपा ने 255 सीटें जीतीं और उसका मत प्रतिशत 41.29 रहा। सपा 111 सीटों और 32.06 प्रतिशत मत के साथ मुख्य विपक्षी दल बन। कांग्रेस केवल दो सीटों तक रह गई। यह आंकड़ा कांग्रेस की मौजूदा चुनौती को साफ करता है। लोकसभा में छह सीटें जीतना राजनीतिक पुनरुत्थान का संकेत हो सकता है, लेकिन 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव साबित करने के लिए केवल लोकसभा का आंकड़ा पर्याप्त नहीं होगा।यही कारण है कि यदि कांग्रेस 125 से अधिक सीटों पर अपना दावा रखती है तो सपा के लिए उसे स्वीकार करना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भी कम सीटों पर समझौता करना राजनीतिक रूप से आसान नहीं होगा। वह उत्तर प्रदेश में लंबे समय बाद संगठन को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बहुत कम सीटें उसे फिर उसी स्थिति में निजी राय बताया। यानी गठबंधन बना रहने की बात अपनी जगह है, लेकिन गठबंधन के भीतर राजनीतिक वर्चस्व की बहस खुलकर बाहर आ चुकी है।

अखिलेश यादव ने इस बयानबाजी को रणनीतिक का हिस्सा बताया है। रायबरेली में उनकी पीडीए यात्रा और उसके जवाब में कांग्रेस की ओर से इटावा, कन्नौज और सैफई में कार्यक्रम की बात भी इसी राजनीतिक रस्साकशी का विस्तार है। सहरयोी दल यदि एक-दूसरे के प्रभाव में सपा यह क्यों चाहेंगी कि जिन सीटों पर केवल मंच तक नहीं रहता, वह सीट बंटवारे की मेज तक पहुंचता है।कांग्रेस की मुश्किल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने उसे उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी का आधार दिया है, लेकिन विधानसभा के आंकड़े उसकी स्थिति को अलग कहानी में रखते हैं। 2024 में सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटें जीतीं। दोनों की संयुक्त संख्या 43 रही, जबकि भाजपा 33 पर रही। सपा का मत प्रतिशत 33.59 और कांग्रेस का 9.46 प्रतिशत था। पांच साल पहले 2019 में सपा के पास पांच और कांग्रेस के पास केवल एक लोकसभा सीट थी। यानी 2024 ने विपक्षी गठबंधन को नई जिंदगी बर्बाद न करें। जिंदगी फिर नहीं मिलती, स्वास्थ्य ही धन हैं।

cm^yk +

नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं: कमिश्नर

■ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन ,चालान होने पर परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई करें



झाँसी जयूस। मण्डलायुक्तबिमल मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित की गयी। मण्डलायुक्त कुमार दुबे की अध्यक्षता में बैठक आयुक्त सभागार में ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि

नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने/ चालान होने पर उसके परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सके, सड़कों पर वाहनों की पार्किंग स्वीकार नहीं होगी। क्योंकि सड़कों पर वाहनों की पार्किंग से यातायात अवरुद्ध होता है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि शहर के विभिन्न चैराहों के आसपास टेम्पो/ई-रिक्शा को चौराहों से न्यूनतम सौ मीटर दूर ही खड़ा किया जाए। ऐसे वाहन जिन पर अनाधिकृत/ अतिरिक्त लाइट लगी हैं, उनके विरुद्ध यह सख्त

कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मण्डलायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों पर व्यवधान उत्पन्न करने वाले रेहड़ी/खोखे आदि को हटाया जाए। एसपी ग्रामीण को निर्देश दिए कि भारी वाहन जिनको शहर में माल उतारना है, उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाए, तथा रात्रि में 11 बजे के बाद ही अनुमति प्रदान करें। मण्डलायुक्त ने बस अड्डे के बाहर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को खड़ा करके सवारी बैठने से मार्ग अवरुद्ध होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये परिवहन निगम को निर्देशित किया। उन्होंने मरीजों के हित में/ जनता की सुविधा के लिए मेडिकल रोड पर एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाकर चालान सम्बन्धित

कार्यवाही सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना की स्थिति में छाष्ट मोंठ व चिरगांव में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता के साथ ही एक रूम जिसमें सभी अपडेट उपकरण भी रखें, दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को समय से उपचार मिले। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बार कोड युक्त इस आशय के बोर्ड लगाए जाएं जिसमें निरक्षरों की चिकित्सालयों की मैपिंग अंकित हो ताकि दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालक उसका प्रयोग कर सकें, यह बोर्ड कैश बैरियर (टोल प्लाजा), ब्लैक स्पाॅट्स व टी जंक्शन्स पर समुचित ऊंचाई पर लगाए जाएं। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि स्कूली वाहनों के अभियान को परिवहन विभाग व शिक्षा विभाग प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करे।

हर वाहन को समस्त विद्यालय परिवहन विभाग द्वारा सृजित पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। इस अभियान के शत-प्रतिशत अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए। मण्डलायुक्त ने सभी नोडल विभागों को निर्देशित किया कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा विभागवार दिये गए निर्देशों तथा जिला व मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में दिये गए निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मण्डल के तीनों जनपदों झांसी, ललितपुर व जालौन में गुड सेमेरिटन योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जिला अस्पताल, मेडीकल कॉलेज, थाना, तहसील, जिला स्तर पर विभिन्न चैराहों पर व्यापक प्रचार-प्रसार करायें जाने के निर्देश दिये, ताकि इस योजना का लाभ

दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर किसी व्यक्ति की जान बचाने में तत्काल प्रयास किया गया हो। बैठक में एसपी ग्रामीण डॉ.अरविन्द कुमार, अपर नगर आयुक्त राहुल यादव, आरटीओ प्रवर्तन राजेश कुमार वर्मा, आरटीओ प्रशासन एके त्रिवेदी, एआरटीओ हेमचंद्र गौतम, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी संजीव कुमार, संयुक्त निदेशक शिक्षा आरके वर्मा, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. आरके सोनी, एड. बेसिक, निदेशक एनएचएआई ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष गुरदीप सिंह चावला, गौरी फाउंडेशन के राहुल द्विवेदी, बस ऑपरेटर एसोसिएशन अध्यक्ष अनूप कुमार, टेम्पो-टैक्सी एसोसिएशन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं एसोसिएशन के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

न्यूज ब्रीफ

शिक्षण संस्थानों में विशेष पॉक्सो विधिक जागरूकता अभियान के तहत आयोजित हुए विधिक साक्षरता शिविर



झाँसी जयूस। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाँसी श्रीमती कमलेश कच्छल के मार्गदर्शन में जनपद के शिक्षण संस्थानों में बच्चों एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु विशेष पॉक्सो विधिक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती ईशा त्रिपाठी के संयोजन में हाफिज सिद्दीक नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज, एम.एस. राजपूत इंटर कॉलेज, नगरा एवं अखंडानंद इंटर कॉलेज, गरीटा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

बीआईईटी झाँसी की डॉ. शहनाज अयूब सम्मानित



झाँसी जयूस। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झाँसी की प्रोफेसर, बुंदेलखंड इनोवेशन एंड इनव्यूवेशन सेंटर फाउंडेशन की निदेशक एवं राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार-2024 से सम्मानित डॉ.(डॉ.) शहनाज अयूब को शोभित विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा विशेषज्ञ वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

मामूली बात पर युवक पर हमला झाँसी जयूस। बबीना थाना क्षेत्र के मथुरा पुरा मंदिर के पास एक युवक पर हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम खजराराह खुर्द निवासी अवधेश राजपूत ने बताया कि उसका बेटा आशीष राजपूत 22 सितंबर को झांसी से घर लौट रहा था। शाम करीब 6 बजे मथुरापुरा मंदिर के पास कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि विपक्षियों ने आशीष से गाली-गलौज की। विरोध करने पर उन्होंने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसे चोटें आईं। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। अवधेश राजपूत की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

कारखाना अधिनियम में इकाई होंगी पंजीकृत

उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण विभागीय अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता: जिलाधिकारी



झाँसी जयूस। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कलैक्ट्रेट नवीन सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति/ व्यापार बंधु सहित जनपद स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई की बैठक ली। कलैक्ट्रेट नवीन सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने उपस्थित समस्त उद्यमियों से कहा कि आपकी समस्याओं का निराकरण ही

समस्त विभागीय अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनपद में औद्योगिक विकास से ही जनपद का चहुंमुखी विकास संभव है। जिलाधिकारी ने उद्योगपतियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बुन्देलखण्ड के चहुंमुखी विकास पर केन्द्रित है,अनेकों योजनायें केंद्र व

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के उद्यमियों को प्राप्त हो रहा है। बुन्देलखण्ड में उद्योगों के सृजन में और तेजी आए और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले,इसके लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित लाभ बुंदेलखंड क्षेत्र के उद्यमियों को मिले, इसे अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

बैठक में जिलाधिकारी ने अध्यक्ष बुन्देलखण्ड चैंबर ऑफ कामर्स सहित मौजूद उद्यमियों से औद्योगिक , व्यापारिक इकाइयों को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने की अपील करते हुए कहा कि श्रमिकों को समुचित न्याय और सुविधायें प्रदान करवाने के लिए इकाई का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। उन्होंने जीएसटी व ईपीएफ विभाग से औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कामगारों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि इकाइयों का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाएगा।

जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने सर्विस स्टेशन व ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भी सूची तैयार करने हेतु उप श्रमायुक्त को निर्देशित किया। जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में डीएम ने मुख्य विकास समस्याओं को सुना, बैठक में ग्रेथ सेंटर औद्योगिक क्षेत्र बिजौली, झांसी के कतिपय भूखंडों में अमल दरामद की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए वेदांत अग्रवाल को ग्रेथ सेंटर फेस- 2 में पहले ध्व-17 भूखंड का आवंटन हुआ था।तत्सम भूखण्डों पर किसानों ने के विरोध के कारण यूपीसीड द्वारा ध्व-04 आवंटन कर दिया।अब पहले भूखंड में लगी बैंक गारंटी जमा है, जो अवमुक्त नहीं हो पा रही क्योंकि नियमानुसार भूखंड पर इकाई स्थापित नहीं हुई है।जिलाधिकारी ने निर्णय लेते हुए उक्त प्रकरण को शासन स्तर पर प्रेषित करने के निर्देश दिए ताकि शासन के निर्देश पर प्रकरण का निस्तारण किया जा सके और उद्यमी द्वारा इकाई स्थापित करने की समस्या का हल निकाल सके।

जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में उपायुक्त उद्योग चौधरी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में जनपद की 04 रैंक और सीएम डैशबोर्ड में,+ श्रेणी प्राप्त हुई है। 2500 लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 3112 प्रेषण तथा 966 आवेदन स्वीकृत करते हुए 893 का वितरण किया जा चुका है। इसी क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जानकारी देते हुए बताया कि जिला समन्वयक व समस्त शाखा प्रबंधकों के साथ दैनिक आधार पर समन्वय स्थापित करते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। योजना सीएम डैशबोर्ड पर+ श्रेणी तथा प्रदेश में टॉप में है। इस मौके पर नगर आयुक्त ए सुदन,सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, एडीएम प्रशासन प्रताप शुक्ल, अपर नगर आयुक्त श्रीमती रोली गुप्ता, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, अध्यक्ष बुन्देलखण्ड चैंबर धीरज खुह्हर लेकिन, दिलीप अग्रवाल, संजय गुप्ता,संतोष साहू सहित अन्य उद्यमी/ व्यापारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

पर्यूर्षण पर्व के समापन पर कलशाभिषेक

समारोह का आयोजन

■ बच्चों का संस्कारित करने वाली शिक्षिकाओं को किया सम्मानित

झाँसी जयूस। पर्यूर्षण पर्व समापन उपरांत जैन समाज की वार्षिक कलश वंदना की श्रृंखला में आज गुदरी स्थित श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर का आयोजन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य विद्यासागर के चित्र अनावरण व दीप प्रज्ज्वलित करके किया। धर्मध्वजा सौरभ जैन, प्रवीण जैन ने स्थापित की। भावपूर्ण मंगलाचरण की प्रस्तुति अर्चना, प्रणति, प्रियंका ने दी। आरंभ में श्री जी की के अभिषेक सुभाष जैन, संजय जैन पुणे, रवि कंधारी, सनत



नायक ने शांतिधारा विवेक नायक, महेंद्र ढ्करई, पंकज जैन, राहुल मान्ची ने की। भगवान के मस्तक पर छत्र चंवर समर्पित किए। महाआरती का अवसर आर के जैन ,वी के जैन को मिला। पर्यूर्षण पर्व के दौरान उपवास रखने वाले श्रावक श्राविकाओं, पाठशाला के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करने वाली शिक्षिकाओं को सम्मानित की को महेंद्र बाबूजी ने सम्मानित किया।

संपूर्ण आयोजन पं. विनोद शास्त्री बबीना के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, परंपर शर्मा, अनुज नीखरा, मुनीश , यश, जयदीप खरे, राजीव सिरसं, बाबूलाल नायक, श्रीमती शीला सिंघई, शोभा जैन, सबिता जैन, सीमा नायक, अंजलि जैन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अंचल जैन ने आभार सनत जैन व धरनेंद्र ने संयुक्त रूप से प्रकट किया।

संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल आरोप लगाना

कांग्रेस की हताशा का प्रतीक: महापौर

■ संवैधानिक विषयों को राजनीतिक ढाल बनाकरभ्रम फैलाया जा रहा है: जिला पंचायत अध्यक्ष

झाँसी जयूस। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता महापौर बिहारीलाल आर्य एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही चुनावी पराजय से बौखलाई कांग्रेस अपनी राजनीतिक नाकामियों को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है।



महापौर द्वारा स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के संयुक्त बयान से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के सभी भ्रामक दावों की पोल खुल चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से एसआईआर सहित सभी चुनावी निर्णय पूरी पारदर्शिता से लिए गए हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी वैध ठहरा चुका है। इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व लगातार ईवीएम,

न्यायपालिका, चुनाव आयोग और सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पवन गौतम जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जब भी विपक्ष जनता की अदालत में पार्जित होता है, वह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर झूठे आरोप

मढ़ने लगता है। कांग्रेस को अपनी संगठनात्मक कमजोरियों पर आत्ममंथन करना चाहिए और देश की संवैधानिक संस्थाओं व जनता से इस झूठे दुष्प्रचार के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। वार्ता में प्रियांशु डे मीडिया प्रभारी एवं मोहित पुरवाल सह मीडिया प्रभारी भाजपा उपस्थित रहे ।

इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन-2026 की नामांकन प्रक्रिया एवं मतदान को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न



झाँसी जयूस। उत्तर प्रदेश विधान परिषद इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन-2026 के नामांकन प्रक्रिया, मतदान एवं अन्य निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/ उप जिला निर्वाचन

अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता जनपद के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट झांसी में आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी

प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन-2026 का निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितम्बर

2026 है। मतदान 23 अक्टूबर 2026 को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना 27 अक्टूबर 2026 को होगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण की जानी है।

उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 10 जनपद प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी एवं ललितपुर सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मण्डलायुक्त, झांसी मण्डल, झांसी हैं तथा अपर आयुक्त (न्यायिक), झांसी मण्डल, झांसी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), झांसी सहित संबंधित अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नामित किया गया है। जनपद झांसी में कुल 47 मतदय स्थल हैं, जबकि सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में 353 मतदान स्थल हैं। जनपद झांसी में कुल 24,934 मतदाता

तथा सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में 2,61,208 मतदाता पंजीकृत हैं। बैठक में उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन से संबंधित कार्य तथा नाम वापसी की प्रक्रिया 29 सितम्बर 2026 से 09 अक्टूबर 2026 तक न्यायालय आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी के कक्ष में संपन्न होगी। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, जिसका सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक है। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में अभ्यर्थी के नवीनतम 5 फोटो (2 सेमी म 2.5 सेमी) प्रस्तुत की जाएगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए

निर्धारित संख्या में प्रस्तावक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए 10 निर्वाचक प्रस्तावक होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय हेतु पृथक बैंक खाता खोलकर उसकी पासबुक की छायाप्रति नामांकन से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। नामांकन के साथ फार्म-26 (शपथ-पत्र) में मांगी गई समस्त सूचनाएं पूर्ण रूप से भरी जाना आवश्यक है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन अवधि के दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए छपवाए जाने वाले पोस्टर, पम्पलेट एवं अन्य प्रचार सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम, पता एवं अन्य आवश्यक विवरण अंकित होना अनिवार्य बताया गया।

नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम 05 व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में उपस्थित रह सकेंगे तथा नामांकन स्थल के निर्धारित परिसर में केवल 03 वाहन अनुमन्य होंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का जुलूस / सभा बिना अनुमति के आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आदर्श आचार संहिता एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है।

स्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक नाथूराम कुशवाहा द्वारा जनता यूनियन प्रेस, शिव परिवार कालोनी, उन्नाव गेट बाहर झाँसी से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक - नाथूराम कुशवाहा* फोन नं. 0510-2331158 आरएनआई नं. यूपीएचआईएन/2007/22191 समस्त विवादों का निपटारा झाँसी न्यायालय के अधीन होगा। *पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए उत्तरदायी